

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय  
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

तारांकित प्रश्न सं : 816  
23 , 2021 प्रश्न सं

वैक्सीन नीति में परिवर्तन

816. श्री :  
श्री :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने समय-समय पर कोविड वैक्सीन को आवंटन और टीकाकरण नीति में परिवर्तन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ख) राज्यों और निजी अस्पतालों को वैक्सीन के वितरण के लिए क्या मानदंड तैयार किए गए हैं;

(ग) अब तक वैक्सीन को पहली और दूसरी खुराक लेने वाले नागरिकों को पृथक रूप से राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(घ) क्या शुक्रात में भारत ने देश में दूसरी लहर के प्रभाव और वैक्सीन की आवश्यकता का आकलन किए बिना वैक्सीन का निर्यात किया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ङ) अब तक खरीद या दान के रूप में विदेशी वैक्सीन को कुल कितनी खुराक प्राप्त हुई है और सरकार द्वारा देश के सभी पात्र लोगों को टीका लगाने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(च) कोविड टीकाकरण के लिए पत्रकारों को अग्रिम पंक्ति के कायकता के रूप में चिन्हित नहीं करने और उन्हें प्राथमिकता नहीं देने के क्या कारण हैं?

३

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ( . प्र )

(क) 16 जनवरी से 30 अप्रैल 2021 तक राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत, भारत सरकार द्वारा 100% वैक्सीन खुराक खरीदी गई थी तथा राज्य सरकारों को निःशुल्क प्रदान की गई थी।

1 मई से 20 जून 2021 तक, “उदारीकृत मूल्य निर्धारण तथा त्वरित राष्ट्रीय कोविड-19 टीकाकरण कायनीति” लागू की गई थी ताकि वैक्सीन निमाताओं द्वारा उत्पादन को बढ़ाया जा सके तथा नई कोविड-19 वैक्सीन को प्रोत्साहित किया जा सके। इस कायनीति के तहत, राज्य / संघ राज्य क्षेत्र तथा निजी अस्पतालों को सीधे विनिमाताओं से कोविड-19 वैक्सीन को खरीद करने की अनुमति थी। भारत सरकार द्वारा घरेलू विनिमाताओं से मासिक वैक्सीन उत्पादन का 50% खरीदी गई तथा राज्य सरकार और निजी अस्पताल शेष 50% खुराक खरीद रहे थे। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र तथा निजी अस्पतालों के लिए उपलब्ध खुराकों की मात्रा 18 से 44 वर्ष की राज्यवार आबादी के यथानुपात आधार पर निकाली जाती थी।

“राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के कार्यान्वयन संबंधी संशोधित दिशा-निर्देश” 8 जून 2021 को जारी किए गए थे यह 21 जून 2021 से प्रभावी होने थे जिसके तहत भारत सरकार देश में उत्पादित कोविड-19 टीकों का 75% खरीदी रही है तथा राज्य / संघ राज्य क्षेत्रों को निशुल्क प्रदान कर रही है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्राथमिकता के अनुसार सभी नागरिकों को निःशुल्क टीका लगाएंगे। घरेलू विनिमाताओं के पास यह विकल्प है कि वह अपने मासिक वैक्सीन उत्पादन का 25% सीधे निजी अस्पतालों को प्रदान कर सकते हैं।

1 मई 2021 से प्राप्त अनुभवों तथा राज्यों से प्राप्त लगातार अनुरोधों के आलोक में दिशा-निर्देशों की समीक्षा की गई तथा संशोधन किया गया।

(ख). भारत सरकार द्वारा निशुल्क प्रदत्त वैक्सीन खुराक राज्य / संघ राज्य क्षेत्रों को लक्षित आबादी के यथानुपात, राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में टीकाकरण की प्रगति तथा वैक्सीन की बबादी जैसे मानदंडों के आधार पर आर्वाटत की जाती है।

(ग). कोविड-19 टीके की पहली और दूसरी खुराक प्राप्त नागरिकों को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या अनुलग्नक में दी गई है।

(घ). भारत सरकार ने देश में वैक्सीनों की उपलब्धता के अनुसार पात्र लाभार्थियों के लिए कोविड-19 वैक्सीन सुरक्षित रखी है। वैक्सीनों की नियात की गई मात्रा में घरेलू विनिमाताओं द्वारा अंतरराष्ट्रीय करारों के तहत कोवैक्स के संबंध में की गई प्रतिबद्धता तथा अन्य देशों / संगठनों को इनको वैयक्तिक प्रतिबद्धता तथा “वैक्सीन मैत्री” पहल के माध्यम से आपूर्ति की गई वैक्सीन शामिल है।

(ङ). आज की स्थिति के अनुसार, भारत सरकार द्वारा दान के रूप में कोई विदेशी कोविड-19 वैक्सीन खरीदी अथवा प्राप्त नहीं की गई है। कोविड-19 महामारी की गतिशील और उभरती प्रवृत्ति के आलोक में, टीकाकरण अभियान की समाप्ति की कोई निर्धारित समय-सीमा दशाई नहीं जा सकती, तथापि, आशा है कि 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी लाभार्थी दिसंबर 2021 तक टीकाकृत हो जाएंगे।

(च). कोविड-19 टीकाकरण समवर्ती वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर राष्ट्रीय कोविड-19 टीकाकरण विशेषज्ञ समूह (एनईजीवीएसी) द्वारा मागर्दाशित है। टीकाकरण संबंधी प्राथमिकता महामारी प्रतिक्रिया तथा स्वास्थ्य प्रणाली की सुरक्षा के उद्देश्य से तथा कोविड-19 से होने वाली बीमारी और मौतों में कमी लाने के लिए तय की गई है। बाद में आयु आधारित प्राथमिकता का अनुपालन किया गया, जिसे न्यायसंगत माना गया और ऐसा पूरी दुनिया में किया गया है।

-19 वैक्सीन को पहली और दूसरी खुराक से टीकाकृत नागरिकों को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र- रु

(20 2021 )

क्र.	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	पहली खुराक	दूसरी खुराक
1	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	1,81,725	79,542
2	आंध्र प्रदेश	1,45,59,253	42,38,908
3	अरुणाचल प्रदेश	6,35,285	1,41,833
4	असम	73,82,885	15,57,222
5	बिहार	1,81,16,037	32,27,229
6	चंडीगढ़	5,49,385	1,43,843
7	छत्तीसगढ़	90,06,605	20,93,764
8	दादरा और नगर हवेली	2,89,431	31,816
9	दमन और दीव	2,25,343	35,733
10	दिल्ली	71,58,176	22,25,291
11	गोवा	9,85,642	2,16,947
12	गुजरात	2,28,50,251	69,02,088
13	हरियाणा	86,33,560	20,62,920
14	हिमाचल प्रदेश	35,42,306	10,65,433
15	जम्मू और कश्मीर	45,86,665	10,36,891
16	झारखंड	68,49,074	15,00,637
17	कनाटक	2,21,88,552	54,08,325
18	केरल	1,21,57,109	49,01,973
19	लद्दाख	1,85,146	62,381
20	लक्षद्वीप	49,064	13,282
21	मध्य प्रदेश	2,15,52,669	41,27,473
22	महाराष्ट्र	3,06,36,740	92,75,340
23	मणिपुर	9,47,072	1,10,389
24	मेघालय	7,88,294	1,26,750

25	मिजोरम	6,14,394	1,37,962
26	नगालड	5,60,660	1,18,686
27	उडीसा	1,13,30,737	32,42,484
28	पुदुचेरी	5,23,893	1,30,293
29	पंजाब	72,59,314	15,58,644
30	राजस्थान	2,32,95,731	57,09,586
31	सिक्किम	4,65,924	1,36,777
32	तमिलनाडु	1,62,14,280	35,36,983
33	तेलंगाना	1,09,41,218	25,12,879
34	त्रिपुरा	21,53,732	7,02,134
35	उत्तर प्रदेश	3,43,94,183	66,57,551
36	उत्तराखंड	40,88,707	12,10,234
37	पश्चिम बंगाल	1,87,51,077	76,74,598
38	विविध	17,42,664	15,38,797
	भारत	32,63,92,783	8,54,53,618